International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक एवं रोजगारपरक शिक्षा का एक अध्ययन

डॉ. धर्मेश श्रीवास्तव[1], डॉ. अजय कुमार गोविन्द राव[2]

सारांश

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी के अतिरिक्त प्रशासन व व्यवसाय जैसे अन्य तत्वों के समाविष्ट हो जाने से इसकी दशा और दिशा में एक गम्भीर परिवर्तन दृष्टिगोचित होता है जिसका मूल उद्देश्य अक्षर ज्ञान से आरम्भ होकर जीविकोपार्जन के किसी साधन तक सीमित होकर रह गया है। जिसके चलते न केवल मनुष्य का सर्वांगीण विकास बाधित हुआ है अपितु इस बाधा ने मानवीय सभ्यता का दमन कर समाज में विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्यों, कुण्ठाओं व वैमनस्य का बीजारोपण भी किया जो आगे चलकर एक वृहद् सामाजिक समस्या का स्वरूप अख्तियार कर चुकी है जिसमें मानवीय मूल्यों व उसकी नैतिक चेतना का हनन, भाषावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवाद इत्यदि पूर्वग्रह से प्रेरित हो नीति/अनीति का निर्धारण, भ्रष्टाचार व विभिन्न रुपों में मानवीय कुकृत्य देखे जाते हैं।

निःसन्देह वर्तमान शिक्षा पद्धति की उपयोगिता के आधार पर अपनी मूलभूत विशिष्टताएँ हैं किन्तु यह विशिष्टता मानव की भौतिक व केवल अर्थिक तत्व के रूप में व्याख्या कर उसे आत्मविहिन यन्त्रवत मानव के तौर पर स्थापित करने की तरफ उन्मुख है, साथ ही इसी भौतिकता से प्रेरित हो समाज में संसाधनों पर आधिपत्य की प्राप्ति व उसे कायम रखने हेतु न केवल सामाजिक कलह को बढ़ावा मिला अपितु विभिन्न वर्गों के रुपमें समाज के वर्गीय संरचना का जन्म भी हुआ। जबकि निश्चित तौर पर शिक्षा की मूल प्रकृति असमानता, विघटन, घृणा व कलह से रहित मानवीय पीढ़ी के भीतर विद्यमान गुणों को विकसित करते हुए उसे पूर्णता प्रदान करना व स्वयं का आत्म साक्षात्कार कराना है।

मुख्य शब्द – राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, व्यावसायिक एवं रोजगारपरक शिक्षा।

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी में राष्ट्रों की प्रगति, विकास और साख का मूल आधार उनकी ज्ञान संपदा ही होगी। यह आधार जितना सशक्त, समेकित, सजगह तथा परिवर्तनों के प्रति सतर्क और गतिशील होगा, राष्ट्र की प्रगति में नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही विस्तृत और सर्वव्यापी होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत की प्राथमिक आवश्यकता हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगी कौशलों की ग्राह्यता से परिपूर्ण शिक्षा पहुँचाने की होगी। ऐसे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 देश के लिए सकारात्मक संभावनाओं के द्वार खोलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आधार सिद्धान्त का वर्णन शिक्षा के व्यापक एवं बहुआयामी महत्त्व को रेखांकित करता है। इसके अनुसार 'शैक्षिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है– जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा एवं सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतना और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित–समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से इस हेतु शिक्षकों और अभिभावकों को तैयार किया है।

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राष्ट्र के शिक्षा सम्बन्धी प्रयास का एक महत्वपूरण तत्व है । व्यासायिक शिक्षा की स्वीकृति देश के आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि को प्रभावित करने में उल्लेखनीय हैं। विशेषतया भारत जैसे देश जहाँ युवाओं के शिक्षित होनें के बावजूद भी उन्हें अपने जीवकोपार्जन के लिए आजीविका की व्यवस्था करने में असफलता प्राप्त होती है। अतरू सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का निर्माण निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक साबित होगा। व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास को इस प्रकार के कदम के लिए मूल्यवान विकल्प के रूप में लिया जा सकता है । व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बदलते उद्योग कौशल की मांग के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है, परिणाम देश को कौशल आपूर्ति और मांग के बीच व्यापक अंतर का सामना करना पड़ रहा है । कौशल के बेमेलपन की समस्या को दूर करने के लिए सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली और उद्योगों के बीच स्पष्ट सम्बन्ध बनाने के माध्यम से प्रभावी और कुशल युक्तियों से व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा और उन्नयन की आवश्यकता है ।

आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक समय और अत्याधुनिक क्षमताओं, उपकरणों सूचनाओं से युक्त रोजगारपरक पाठ्यक्रम हैं, इसकी प्रासंगिकता या शैक्षिक निहितार्थ सार्वभौमिक है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होने के साथ–साथ उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करते हुए उन्हें स्वयं का रोजगार स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। अतः वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा को ध्यानगत रखते हुए अध्ययनकर्त्ता ने अपने विषय का चयन किया गया है।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्यों एवं सुझावों का अध्ययन –

व्याख्या–

व्यावसायिक शिक्षा हमारे भारतीय शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक स्रोत है। भारतीय शिक्षा को सन्दर्भ को बदलने में व्यावसायिक शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का कार्यक्रम 1976 में आरम्भ किया गया। परन्तु शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना ने अभी गति नहीं पकड़ी है। इस धीमी प्रगति के बहुत से कारण है– जैसे– अच्छी समन्वित प्रबन्ध पद्धति की कमी, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए बेरोजगारी, माँग एवं आपूर्ति में सामंजस्य न होना, समाज द्वारा इस अवधारणा को स्वीकार करने की अनिच्छा, अतः व्यावसायिक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्काल कदम उठाना अति आवश्यक है।

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को नियोजित तथा कार्यान्वित करने में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों, उत्तर प्राथमिक, उत्तर माध्यमिक एवं उत्तर–उच्चतर माध्यमिक स्तरों में अपेक्षित परिवर्तनों के अनुरूप क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि एक प्रभावशाली प्रबन्धन पद्धति संगठित की जाये। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाने वाली वह शिक्षा है जिससे छात्र अपनी +2 की शिक्षा पूरी करने के बाद वास्तविक जीवन में प्रवेश के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी व्यवसाय या रोजगार को अपना सकें तथा धन अर्जित कर सकें।

व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक वृद्धि एवं उनके रोजगार में उन्नति के अवसरों की कमी। व्यावसायिक शिक्षा के विरूद्ध धारण किये गये पूर्वाग्रह तब तक दूर नही होगें जब तक माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को लाभप्रद रोजगार के उचित अवसर अथवा शिक्षा व्यावसायिक या सामान्य कार्यक्रमों में आगे जाने की सुविधाएँ प्रदान नहीं की जायेंगी। ऐसे कार्यक्रमों में डिप्लोमा विशेष डिग्री पाठ्यक्रम, व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है।

इक्कीसवीं सदी में राष्ट्रों की प्रगति, विकास और साख का मूल आधार उनकी ज्ञान संपदा ही होगी। यह आधार जितना सशक्त, समेकित, जगह तथा परिवर्तनों के प्रति सतर्क और गतिशील होगा, राष्ट्र की प्रगति में नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही विस्तृत और सर्वव्यापी होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत की प्राथमिक आवश्यकता हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगी कौशलों की ग्राह्यता से परिपूर्ण शिक्षा पहुँचाने की होगी। ऐसे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 देश के लिए सकारात्मक संभावनाओं के द्वार खोलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आधार सिद्धान्त का वर्णन शिक्षा के व्यापक एवं बहुआयामी महत्त्व को रेखांकित करता है। इसके अनुसार 'शैक्षिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है– जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा एवं सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतना और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित–समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से इस हेतु शिक्षकों और अभिभावकों को तैयार किया है। इस शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो राष्ट्र की शैक्षिक आवश्यकता और शिक्षा के समावेशी चरित को आगे बढ़ा सके। शिक्षा के अन्तर्गत उसकी सर्वसुलभता, सक्षमता निर्माण, कौशल विकास तथा गुणवत्ता का तत्त्व समाहित हो।

नई शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रावधान किये गये हैं–

- 5 प्रतिशत से भी कम भारतीय कार्यबल ने औपचारिक अवकाश शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा संरचना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि एक राष्ट्र के रूप में हम अधिक उन्नत और विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है।
- चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना, जिसमें मध्य और माध्यमिक विद्यालय में कम उम्र में व्यावसायिक प्रदर्शन की शुरुआत शामिल है। (एनईपी पैरा 16.4)।
- कक्षा 6 से शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रावधान किया गया है ताकि व्यवसाय के प्रति सही धारणा और दृष्टिकोण विकसित हो सके। आप कह सकते हैं कि यह व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक स्थिति के पदानुक्रम को दूर करने के लिए किया गया प्रयास है।
- द्वितीय. 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा, जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी (पैरा 16.5)। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा संस्थान तकनीकी संस्थानों जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक, कुछ स्थानीय उद्योगों आदि के साथ

सहयोग करेंगे। इन कदमों से छात्र व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और किसी विशेष व्यवसाय के प्रति अपने कौशल और रुचि विकसित करने में सक्षम होंगे और इसमें महारत हासिल कर सकेंगे।

- श्लोक विद्या– यानी भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। (एनईपी पैरा 16.5)। हमारी संस्कृति से दिन–ब–दिन लुप्त होती जा रही लोकविद्या को कायम रखने के लिए विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से विभिन्न स्थानीय विशेषज्ञों की पहचान की जाएगी और उनके तहत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप कार्यक्रम का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका होगा। स्थानीय व्यावसायिक शिल्पों की पहचान की जाएगी और छात्र उनके शिल्पों का पता लगाएंगे और इन स्वदेशी प्रथाओं के बारे में इंटर्नशिप आयोजित की जाएगी। उनकी कई प्रथाएं हैं जो अनोखी हैं और केवल भारत में ही प्रचलित हैं। इन कलाओं और प्रथाओं को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए और इसमें कम उम्र में इंटर्नशिप मददगार हो सकती है।
- व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को केवल नियमित स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश भी की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने कौशल विकसित कर सकें और अपने वांछित लक्ष्यों को पूरा कर सकें।
- व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए फोकस क्षेत्रों को कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के मानचित्रण के आधार पर चुना जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया) इस प्रयास की निगरानी के लिए व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति (एनसीआईवीई) का गठन करेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और उद्योग के सहयोग से सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। (एनईपी पैरा 16.6)। छात्रों को सूचित करियर विकल्प चुनने में मार्गदर्शन के लिए आठवीं कक्षा में व्यावसायिक रुचि सूची और दसवीं कक्षा में कौशल आधारित योग्यता परीक्षण (एसबीएटी) की शुरूआत। इससे छात्रों को सही करियर विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और उन्हें उनके कौशल और रुचि के अनुसार निर्देशित किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्रदान किये जा रहे विभिन्न रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन–

व्याख्या–

आज रोजगार एक गंभीर समस्या है। किसी तरह लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं और बेरोजगार या अल्परोजगार हो जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सीधे उपलब्ध संसाधनों से जुड़ी हुई है और सरकार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए संसाधन आवंटन में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान से सशक्त बनानाहोना चाहिए। छात्रों के बौद्धिकस्तर के निर्माण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

छात्रों को रोजगारपरक और जीवन को प्रशिक्षित करने वाली शिक्षा देनी चाहिए।शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक छात्र व्यावहारिक जीवन में चुनौतियों का अधिक कुशलता से सामना करने में सक्षम होना चाहिए।यद्यपि हर साल छात्रों और कार्यक्रमों की संख्या बढ़ रही है, भारत निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने में विफल रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी से बचना चाहिए। केंद्र सरकार को नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने, पूरी व्यवस्था में सुधार करने और शिक्षा प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए। इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को चरित्र के साथ मिश्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ जीवन में सीखने, बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। एक जीवंत राष्ट्र का निर्माण ऊर्जावान युवाओं और सक्रिय मीडिया से होता है।

नई शिक्षा नीति के 'आत्म– निर्भरता' संबंधी लक्ष्यों में एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह नीति प्राचीन शिक्षा प्रणालियों के आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के साथ समायोजन की परिकल्पना करती है जिसका तात्पर्य यह है कि हम वर्तमान शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग मानव जीवन के उन सारभूत लक्ष्यों की सिद्धि के लिए करें जो प्राचीन काल से सफल मानव जीवन के प्रतिमान के तौर पर प्रयोग होते आए हैं जैसे– पृथ्वी के समस्त जैविक–अजैविक तत्वों को एकसार मानने की शिक्षा ने भारतीय समाज को प्रकृति का सम्मान करने और उसकी रक्षा का दायित्व वहन स्वीकार करने की प्रेरणादायी है। इस शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग वर्तमान की पर्यावरणीय समस्याओं के निदान हेतु किया जा सकता है। वस्तुतः मानव तथा प्रकृति का सहअस्तित्व ही भारतीय–जीवनका सार तत्व है और नई शिक्षा नीति इस सहअस्तित्व को कायम रखने में सहायक होगी।

अब अगर शिक्षा नीति के एक अन्य आयाम सशक्तिकरण की बात की जाए तो इसकी शुरुआत करने के संदर्भ में 'मैथिलीशरण गुप्त' की एक कविता बहुत प्रासंगिक जानपड़ती है–

हां! आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण होकर क्लिष्ट है
कुलपति सहित उन गुरुकुलों का ध्यान ही अवशिष्ट है
बिकने लगी विद्या यहां अब शक्ति हो तो क्रय करो
यदि शुल्क आदि ना दे सको तो मूर्ख बनकर ही रहो।?

यह कविता वस्तुतः शिक्षा के व्यवसायीकरण पर कटाक्ष करती है क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण का सीधा अर्थ है शिक्षा तक वंचित वर्गों की पहुंच ना होना, जो आगे चलकर समाज के सशक्तिकरण में बाधक सिद्ध होता है। यहां समाज के सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम लिए जा सकते हैं जिनमें वंचित वर्गों का सशक्तिकरण मुख्य है जिसके अंतर्गत महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाना, दिव्यांग–जनों का कल्याण, अल्पसंख्यकों का कल्याण, ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाना शामिल है। वस्तुतः इन समुदायों को सशक्त बनाने की परिचर्चा जहां कहीं भी होती है तो उसका तात्पर्य शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा, गरिमा पूर्ण जीवन तक इन वर्गों की पहुंच से होता है, और अगर इन अवसरों की प्राप्ति के मुख्य साधन की बात करें तो हम शिक्षा की पहचान मुख्य कारक के तौर पर कर सकते हैं क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रोजगार प्राप्ति में सहायक है, रोजगार की सुरक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा पूर्ण जीवन की प्राप्ति में सहायक है, जो आगे चलकर व्यक्ति तथा समाज के सशक्तिकरण में सहायक होगी।

निष्कर्ष–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्यों एवं सुझावों का अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष–

निष्कर्ष–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में सीखने के विभिन्न चरणों में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण उद्योग की मांगों के अनुरूप है और स्नातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ा सकता है। व्यावहारिक कौशल पर यह जोर छात्रों को नौकरी बाजार की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करता है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्रदान किये जा रहे विभिन्न रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन का निष्कर्ष–

निष्कर्ष–

नई शिक्षा नीति–2020 को लागू करने का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। NEP–2020 के तहत पाठ्यक्रम के साथ–साथ छात्र स्व–रोजगार से सम्बंधित विषयों को भी सीखेंगे। इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। नई शिक्षा नीति में देश द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रमों में 30 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा परिष्कृत करने का भी अधिकार है। इस नीति में विभिन्न संस्थाओं को स्वायतत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत की संस्कृति के द्योतक संगीत, कला आदि को इसमें किसी न किसी रूप से प्रमुखता से रखा गया है। इस नीति में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की योजना है। इस नीति के तहत स्नातक छात्र (4 वर्षीय) सीधे पी–एच0डी0 में प्रवेश ले सकते हैं। जिससे भारत का विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं कला में सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकेगा। इस नीति के तहत 10+2+3 शिक्षा को 5+3+3+4 में संशोधित करने की योजना है। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को छोड़कर चले जाने वाले छात्र दुबारा उस शिक्षा को कुछ शर्तो के साथ शुरू कर सकेंगें।

1. इस नीति में पढ़ाई बीच में छूट जाने पर, बाद में उसको पूरा करने की भी योजना हैं। साथ ही साथ पढ़े गये कक्षाओं का प्रमाण पत्र मिलेगा।
2. नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञान विषयों का अध्ययन करने वाला छात्र कला के विषयों को भी चुन सकेगा।
3. नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने एवं कम्प्यूटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके शिक्षा को और भी सरल करने की योजना है।
4. इस नीति में कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करने की योजना है, जिसके तहत सभी शिक्षण संस्थाओं को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।
5. इस शिक्षा नीति में शोध एवं अनुसंधान को लेकर विशेष सुविधाएं दी गयी है। कोई भी विद्यार्थी स्नातक के बाद ही शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है। जीवन स्तर को सुधारने में भी यह शिक्षा उपयोगी साबित होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना, साइटेट इन सिंह, बिरेंद्र एवं देवी, कुकन (2022), उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, इण्टरेनशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड एनॉलिटिकल रिव्यूस, वॉ0 9, इश्शू–1, पृ0 17–20
2. कुमार, प्रकाश : 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020।
3. कुरैन, अजय, चन्द्रमना, बी, सुदीप (दिसंबर 2020). इंपैक्ट आफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन हायर एजुकेशन,
4. सिंह, रेनू एवं सिंह, नागेन्द्र कुमार (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी–2020 : इम्पालबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराज : चन्द्रा ब्रदर्स।
5. मिश्र, आलोक कुमार (2023). मनुस्मृति में निहित आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन शिक्षा का नयी शिक्षा नीति–2020 में समालोचनात्मक अध्ययन, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी–2020 : इम्पालबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराज : चन्द्रा ब्रदर्स।

6. यादव, जितेन्द्र प्रसाद एवं पाण्डेय निशा (2023). नई शिक्षा नीति–2020 : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी–2020 : इम्पालबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराज : चन्द्रा ब्रदर्स।
7. गुप्ता, विजय कुमार (2023). व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में नई शिक्षा नीति : 2020 : एक अध्ययन, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी–2020 : इम्पालबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराज : चन्द्रा ब्रदर्स।
8. गुप्ता, सुजीत कुमार (2023). उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन में कठिनाइयों एवं चुनौतियाँ, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी–2020 : इम्पालबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराज : चन्द्रा ब्रदर्स।